

बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर 2025: पार्ट-1

(Translated by Google)

विषय: बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर 2025 बनाम जरूरत

के मैनेजमेंट सिस्टम को धर्म (मूल धर्म) के हिसाब से बदलना और धर्म संस्थानों (धार्मिक संस्थाओं) को फिर से बनाना ताकि भारत के सभी नागरिकों और असली मेहमानों को एक सिस्टमैटिक और टाइम फ्रेम में पूरी सोशल सिक्योरिटी (यानी फिजिकल सेफ्टी, और हवा, खाना, पानी, कपड़ा, रहने की जगह, शिक्षा, सेहत, न्याय, मनोरंजन और नौकरी के मौके और क्रिएटिविटी दिखाने वगैरह की सिक्योरिटी) का ध्यान रखा जा सके - बिहार और पूरे भारत के लोगों का टेंशन कम करने के लिए कंसल्टेंसी देने के लिए (खुद से) दिलचस्पी दिखाना, एक प्रैक्टिकल तरीका -- इस बारे में

CC: जरूरी कार्रवाई के अनुरोध के साथ पढ़ने के लिए,

1. महामहिम सुश्री द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति,
2. महामहिम श्री सी.पी. राधाकृष्णन, भारत के उपराष्ट्रपति
3. माननीय श्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री,
4. माननीय श्री ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष
5. माननीय श्री अमित शाह, गृह मंत्री,
6. माननीय श्री एस. जयशंकर, विदेश मंत्री
7. माननीय श्री सुमन बेरी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष,

भारत के सम्मानित साथी नागरिकों

इस विषय पर ये जानकारी दी गई है, इसमें शामिल हैं (A). बड़ी आउटलाइन, (B). प्रपोजल की समरी, (C). अंतिम प्रस्तुतिकरण,

(ए) व्यापक रूपरेखा

A.1). इंटेलेक्चुअल क्लास में इस बात पर चर्चा हो रही है कि: बिहार में असेंबली इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन एक नेगेटिव (ज़ीरो भी नहीं) गेम है, जहाँ बिहार के साथ-साथ भारत में भी हर कोई हारता है, चाहे कोई भी जीते और MLA बने और कौन सब मिलकर सरकार बनाए और मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बने।

इसके अलावा इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव नेताओं का खुद को और अपने समर्थकों को बेवकूफ बनाने का एक खुद का जुनून है और यह बिहार के लोगों की कोशिश का एक

और दौर है ताकि वे धोखा खाने, लूटने, बीमार होने और बेवकूफ बनने के बजाय कुछ सुकून पा सकें और फिर निराशा और लाचारी की भावना से घिरे रहें।

इसके अलावा, इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव एक कबाड़ के सौदागरों और चालाकी के उस्तादों की बिहार और पूरे भारत को कबाड़खाना और जानवरों की दुनिया में बदलने की होड़। बिहार और भारत और दुनिया की मौजूदा हालत का गहराई से एनालिसिस, साथ ही सुधार के लिए कंसल्टेंसी का ऑफर नीचे दिए गए पॉइंट्स में दिया गया है।

A.1.1). नीचे साइन करने वालों को नहीं लगता कि यह आर्टिकल 06.11 और 11.11.2025 को होने वाली मौजूदा चुनाव विधानसभा की वोटिंग पर किसी भी तरह से असर डालेगा, लेकिन उम्मीद है कि यह आर्टिकल बिहार के साथ-साथ पूरे बिहार में इस बात पर ज़रूर चर्चा शुरू करेगा कि देश और लोगों की तरक्की और विकास के लिए सभी अट्ठाईस राज्यों में ऐसे चुनाव कराना और उन्हें बनाए रखना ज़रूरी है।

A.2). नीचे साइन करने वाले, नरेंद्र अग्रवाल (उम्र 59 साल), ग्रुप (रिसरैक्शन ऑफ़ धर्म) के मुख्य व्यक्ति, भारत के असली निवासी हैं, जिनकी छोटी प्रोफाइल सोशल साइट LinkedIn/Facebook, या हमारी वेबसाइट: resurrectionofdharma.com से देखी जा सकती है।

इसके अलावा, वेबसाइट पर नीचे दिए गए हस्ताक्षर भी दिखाए गए हैं तैयारी फ्री में डाउनलोड होने वाली किताबों (जो मैंने लिखी या एडिट की हैं), ओपन लेटर और उनमें दिए गए इंटरव्यू और पॉडकास्ट के लिंक के ज़रिए सब्जेक्ट कंसल्टेंसी देने के दावे के पीछे यह बात है। इसके अलावा, तैयार रेफरेंस के लिए दो पॉडकास्ट के लिंक नीचे दिए गए हैं:

<https://youtu.be/FD21cRfBmjs?si=w4wYpanTGR0fWiRH>,

और, <https://youtu.be/-8H6j9mmY5M?si=eKI22EBfQlaNKzD5>,

इसके अलावा, नीचे साइन करने वाले को देश का अनुभव है और उन्होंने साल 2019 से दिसंबर 2024 तक पूरे देश में घूमा और ज़्यादातर अकेलेपन में रहे। वे यह बताना चाहते हैं कि वे कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट नहीं हैं और कंसल्टेंसी का यह ऑफर कुछ जाने-माने संतों, साधुओं, साध्वियों, एक्सपर्ट्स और मास्टर्स के कहने पर दिया जा रहा है ताकि हिमालय से लेकर भारत के मैदानों और हिंद महासागर तक हमारी सभ्यता की शान को वापस लाया जा सके, और पूरी दुनिया के इंसानों को प्रकृति के साथ रहने और हेल्दी, खुश और पवित्र ज़िंदगी जीने के लिए गाइड किया जा सके।

A.3). पिछले दो-तीन हजार सालों में भारत में क्या हुआ, उसके कारण और साज़िशें क्या थीं, इसकी ज़्यादा डिटेल में जाए बिना यह साफ़ कहा जा सकता है कि जिस तरह से भारत में घटनाओं का मोड़

आया, उसमें यह भी जोड़ा जा सकता है कि भारत ने इतने नखरे, उथल-पुथल और उथल-पुथल देखे हैं जो किसी और देश ने नहीं देखे/अनुभव नहीं किए। इसी वजह से भारत इतना काबिल है कि वह समाज और देश को चलाने और मैनेज करने के तरीके में ज़रूरी बदलावों के बारे में सोच सके, प्लान बना सके और उन्हें लागू कर सके। साथ ही, वह अपने नागरिकों को एक ऐसा प्लैटफॉर्म दे सके जहाँ वे एक हेल्दी, खुशहाल और पवित्र ज़िंदगी जी सकें और दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकें, ताकि वे भी वैसा ही करें और उस लय का आनंद लें जो यह देगा।

यहां, यह ध्यान देने वाली बात है कि हालांकि दुनिया के कई दूसरे देश भी ऐसे ही बदलाव देख रहे हैं, लेकिन उन्हें यहां बताए जा रहे बदलाव को एक्सपेरिमेंट करने के लिए सही देश नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन देशों में रहने वाले ज़्यादातर लोग धर्म से भटक गए लगते हैं, यह परपेच्युटी (बेसिक धर्म जिसे संस्कृत में धर्म सनातन कहते हैं) और उसके अधिकारों, ज़िम्मेदारी और इनकम/यील्ड/रिसोर्स के बंटवारे का सिस्टम है, जिसकी यादें भारत आज भी बनाए रखने के लिए खुशकिस्मत है। भारत में असल में धर्म को फिर से ज़िंदा करने और धर्म संस्थान बनाने, बुरी ताकतों को खत्म करने और सही/संत ताकतों को ऊपर उठाने की ज़रूरत है, जिसका ऐतिहासिक रूप से, भारत के ही सीता-राम एक उदाहरण हैं जिन्होंने बहुत चर्चित राम राज्य की स्थापना की।

A.4). जब किसी देश के लिए ब्रेन ड्रेन, मनी ड्रेन, फेवरिटिज्म और करप्शन जैसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगता है, तो इसका मतलब है कि देश में चेक और बैलेंस बनाए रखने वाले ज़रूरी इंस्टीट्यूशन बहुत पहले ही साइडलाइन हो चुके हैं और उन्हें बंद कर दिया गया है या वे बंद हो गए हैं। यह देखा जा सकता है कि अगर देश के ज़रूरी इंस्टीट्यूशन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि देश की कलेक्टिव लीडरशिप (चाहे वे सत्ता में हों या विपक्ष में) या तो इनएफिशिएंट है या करप्ट है या दोनों (इनएफिशिएंसी या करप्शन में से एक अच्छाई दूसरे को जन्म देती है)।

अगर लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेटर, जज वगैरह में ये इनएफिशिएंसी और करप्शन के लक्षण कई इलेक्शन के बाद भी बने रहते हैं, तो यह पक्का है कि लीडरशिप के सिलेक्शन या इलेक्शन के प्रोसेस में ही गलती है, जो आगे यह भी दिखाता है कि यह टीचर और उनके मास्टर और उनके एजुकेशन देने और समाज और देश को बनाने के तरीके की गलती है।

अगर टीचर और मास्टर ही गलती कर रहे हैं तो यह पक्का है कि इलाके की आध्यात्मिक समझ ही गड़बड़ा गई, साधु-संत जंगलों या पहाड़ों पर अकेले चले गए और चालाक कला के उस्ताद खाली या बची हुई जगह में घुस गए। हालांकि इस पर कोई बहस कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इकोनॉमिक्स के बेसिक सिद्धांत यह कैसे भूल गए कि इकोनॉमिक्स साइंस और आर्ट पर संधियों का कलेक्शन है, "इको- पर्यावरण- इकोसिस्टम" की भावना और विश्वास है और भारत को इस हालत में ले आया जहां खेती के लिए पेड़ और जंगल काटे गए और खेती की जगह बंजर सड़कें, एयरपोर्ट, होटल

और उससे जुड़ा टूरिज्म आ गया, जिसने मिलकर देश को इस हालत में पहुंचा दिया और अपने ही बच्चों को इतना दुखी बना दिया कि 80 करोड़ लोगों (पचास परसेंट से ज़्यादा आबादी को हर महीने फ्री राशन देना पड़ रहा है) को।

भारत को इस जानकारी से कुछ तसल्ली मिल सकती है कि इस दुनिया में सिर्फ वही नहीं है जो इस स्टेज तक पहुँचा है, बल्कि सच तो यह है कि दुनिया के लगभग सभी देश किसी न किसी स्टेज पर नीचे की ओर जा रहे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले तीन हजार सालों में अब तक की सभी इकोनॉमिक थ्योरी - "बार्टर सिस्टम से लेकर सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी से लेकर लेटेस्ट "नियो क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी" तक - फेल हो गई हैं, जिससे इसे करने वाले लोग मुश्किल में पड़ गए हैं और उन्हें या तो नई थ्योरी बनाने या नेचर की बेसिक और हमेशा रहने वाली इकोनॉमिक्स पर लौटने का मौका ही नहीं मिला है।

भारत (और दूसरे देशों) में इस बुरी हालत की अच्छी बात यह है कि इस समय सभी मनमौजी, मनगढ़ंत आइडिया गायब हो जाते हैं, सरकारी कर्मचारियों, पॉलिसी बनाने वालों और ज्यूडिशियरी के सपने और मीठे सपने गायब हो जाते हैं और लोग असलियत को मान लेते हैं और बेसिक चीज़ों के साथ ज़िंदगी फिर से शुरू करने को तैयार हो जाते हैं।

A.4.1). नीचे कुछ पैरामीटर दिए गए हैं जिनसे कोई भी आम आदमी यह पता लगा सकता है कि भारत की ज़मीनी हकीकत अच्छी हालत में नहीं है:

(a) प्रधानमंत्री ऑफिस ने खुद माना है कि भारत में 80 करोड़ (भारत की 60 परसेंट आबादी) लोग गरीब हैं और उन्हें फ्री राशन मिलना चाहिए। (जैसा कि: <https://www.india.gov.in/spotlight/pradhan-mantri-garib-kalyan-package-pm-gkp>, india.gov.in, भारत का नेशनल पोर्टल है)।

इसके अलावा, भारत सरकार करोड़ों गरीब माने जाने वाले किसानों को तीन-चार किशतों में सिर्फ लगभग छह-आठ हजार रुपये ही मानदेय के तौर पर देती है, जबकि देश खुद को खेती-बाड़ी वाला देश बताता है।

(b) ऐसा लगता है कि कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है; भारत की राजधानी दिल्ली समेत किसी भी मेट्रो में अनगिनत भिखारी मिल जाएंगे।

(c). न्याय मिलने में कितना समय लगता है, (भारत के अलग-अलग कोर्ट में चार करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग हैं, जिनमें से 90 हजार से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं)? इसके अलावा, शोषण की शिकायत

करने और राहत पाने का कोई रास्ता नहीं बचा है (चाहे वर्कर द्वारा या मालिक द्वारा और रिश्तों में भी)।

(d) शिक्षा, बीमारी से ठीक होने और कोर्ट से न्याय पाने पर खर्च किया गया पैसा, और स्वास्थ्य और अच्छी आदतों, मनोरंजन और जश्न पर खर्च किया गया पैसा?

(ई). जंगल और पानी की जगहों की हालत, ताज़ी हवा और पानी की क्वालिटी?

(f) कॉलोनियों, बाज़ार और धार्मिक जगहों पर शोर का लेवल बहुत ज़्यादा है।

(g). ऐसा लगता है कि संतों/साधुओं/फकीरों, गुरुओं और पुजारियों, बुजुर्गों और नेताओं का उन पर से भरोसा उठ गया है, नतीजतन समाज में उनकी इज़्ज़त चली गई है, इसलिए वे अपने गुज़ारे के लिए पैसा जमा करने को मजबूर हैं?

(h) घर से दूर किसी जगह पर मुश्किल आने पर छोटी-मोटी मदद (जैसे आने-जाने के खर्च के लिए पैसे) मांगने का कोई तरीका नहीं है , उसी तरह छोटे-मोटे शोषण के लिए रिपोर्ट करने और तुरंत सुकून पाने का भी कोई तरीका नहीं है।

(i) दुनिया की दूसरी करेंसी के मुकाबले इंडियन करेंसी की वैल्यू क्या है?

(जे). नेताओं के लगातार बदलते रुख?

(K). 'परिवार, समाज, योग, धर्म-निरपेक्ष, सेक्युलर, और दुनिया एक बड़ा परिवार है (वसुधैव कुटुम्बकम्)' जैसे बुनियादी शब्दों का मतलब गलत समझा गया है?

(एल). ऐसा लगता है कि कोई मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं है स्थानीय स्तर पर हम जो खाना खाते हैं, जो लिक्विड पीते हैं, जो चीज़ें स्मोक करते हैं और जो चीज़ें पढ़ते और देखते हैं, वे असल में नागरिकों, उनके समाज और देश को आकार देती हैं।

(n). साफ़-सफ़ाई, मनोरंजन और नैतिकता वगैरह सिखाने के क्षेत्र में बिज़नेस एक्टिविटीज़ में सुस्ती दिख रही है।

A.4.2). क्योंकि विश्वास हर जीव के लिए जन्मजात और दिल का केंद्र होता है, इसलिए जब विश्वास डगमगाता है तो यह साफ़ है कि दिल ठीक से काम नहीं करेगा। मेडिकल डेटा इस बात की पुष्टि करता है कि बीमारियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, जो साफ़ तौर पर दिखाता है कि समाज में उम्मीद जगाने वाली एजेंसियाँ (धार्मिक संस्थाएँ) अपने मानने वालों में उम्मीद जगाने में बुरी तरह नाकाम हो रही हैं। क्या समाज के लिए इससे बुरी हालत हो सकती है कि कम से कम उम्मीद न हो?

A.5). चीन ने अपनी पुरानी समझ और "ताओ-द वे" की परंपरा को आगे बढ़ाया [जो सिखाता है कि हर चीज़ की जड़ में एक ही सच है और इसका मतलब है-द वे जिसे सबसे अच्छे से "ताओ ते चिंग" किताब में दी गई 81 कविताओं/विषयों को समझकर समझा जा सकता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे लाओ त्ज़ू ने लगभग 2600 साल पहले (571 BC) लिखा था], और अब पहले माओइज़्म और फिर ज़ियाओइज़्म (1970 के बाद डेंग ज़ियाओपिंग के तरीके) तक पहुँच गया है।

ताओ धर्म के विपरीत जो कहता है कि:

"मज़बूती से बने फ्लेक्सिबल सिस्टम लंबे समय तक चलते हैं", ताओ के अनुसार ये नियम लोगों को खुश करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यह सबसे अच्छा तरीका है जो एक शासक राज करने के लिए कर सकता है, बल्कि इसलिए है क्योंकि इन सिस्टम को प्रजा - यानी आम जनता - अपनाती है, उनका सम्मान करती है और उनकी रक्षा करती है। माओइज़्म और ज़ियाओइज़्म (डेंग ज़ियाओपिंग की तरह) को राज करना मुश्किल लगता था क्योंकि वे भूल गए थे) गहरी जड़ें जमाए हुए और दूर तक पहुंचने वाले मूल गुणों को छोड़ दिया और इस जोड़ी (माओ और डेंग) ने "मार्क्स और लेनिन की ढीली-ढाली थ्योरी और प्रैक्टिस के आधार पर ढीले-ढाले नॉर्म्स पर पक्के सिस्टम बनाने की कोशिश की। इसका नतीजा यह होता है कि एक शासक यह भूल जाता है कि:

"आम लोग स्वार्थ और डर से काम करते हैं,

बुद्धिमान लोग विश्वास और आपसी भरोसे से काम करते हैं।

इसके अलावा, इन फाउंडर्स (माओइज़्म और ज़ियाओइज़्म) ने खुद को मैटेरियलिज़्म (मैटेरियलिस्ट प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सों में तोड़ने और ज़्यादा कमाने के लिए रूल बुक को मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं) और बागियों (बागी आम तौर पर रूल बुक को जलाने की कोशिश करते हैं और फिर अराजकता लाते हैं) के आगे सरेंडर कर दिया है, जिसने मिलकर चीनी समाज की सेंसिटिविटी को कमज़ोर कर दिया है, जब चीन अपने लोगों को एक बच्चे का नॉर्म अपनाने के लिए मजबूर करता है।

इस एक बच्चे के नियम की वजह से चीन में लोगों में असुरक्षा और असंवेदनशीलता बढ़ी है। इसके अलावा, इस एक बच्चे के नियम ने चीन में परिवार और समाज में भी काफी खालीपन पैदा कर दिया है (कोई भाई-भाई, भाई-बहन, बहन-बहन नहीं, कोई मामा-मामी, मौसी और भाई, बहन, चाचा-चाची के दोस्त नहीं), क्योंकि प्रकृति को खालीपन पसंद नहीं है, इस जगह को पैसे और भौतिक चीज़ों को

इकट्ठा करने से भर दिया गया और लोगों को अपनी तरफ सोचने वाला और खुद पर ध्यान देने वाला बना दिया गया।

अफसोस! चीन अपनी विरासत में मिली दुनियावी समझ और सबको साथ लेकर चलने की सोच से हटकर दुनियावी ज्ञान और इंसानी सोच की तरफ बढ़ गया है। चीन ने अपनी तरक्की और विकास के लिए बहुत ज़्यादा और पागल करने वाली इमोशनल कीमत चुकाई है। चीन की तरक्की और विकास में अनगिनत चीनी लोगों का श्राप शामिल है, इतना ज़्यादा कि इसका असर उन सभी पर पागल करने वाला होता है, (जो भी) इसका फल चखता/खाता है।

कुछ हलकों में यह चर्चा में रहा है कि चीन असल में किस जाल में फंस गया है, वे कहते हैं कि जहां: "ताओ- रास्ता है, माओ ज़्यादा रास्ते हैं, शिओ- कोई रास्ता नहीं है, X गुणा भी है और नकार भी", चीन का आगे का सफ़र असल में टेढ़े-मेढ़े में खत्म हो रहा है।

चीन में ऐसे हालात में, हमारे लिए (या किसी और के लिए) किसी भी तरह की सही मदद और सहयोग की उम्मीद करना दुख की बात होगी। बल्कि यह न सिर्फ़ वह समय है जब सभी को चीन को ठीक करने में मदद करनी चाहिए, बल्कि यह एक बुनियादी इंसानी फ़र्ज़ है कि हम चीनियों को उनकी गलत तरीके से मिली इनसिक्वोरिटी और इनसैसिटिविटी से उबरने में मदद करें और ताओ के उनके पुराने ज्ञान की सच्ची विरासत बनें।

A.6). पश्चिम यह बकवास करने में लगा है कि दो भाईचारे वाले विश्व युद्ध लड़ने के बाद भी इंसानी खून और चमक की उसकी प्यास और भूख शांत नहीं हुई है; बल्कि यह हर दिन बढ़ती ही जा रही है। कोई भी समझ सकता है कि इन पश्चिमी देशों की सैटेलाइट इंडस्ट्री अभी भी डिफेंस प्रोडक्शन की हैं, और इसी से वे अपनी भाषा में गुमराह करने वालों को काबू में करने के लिए अपनी फायर पावर बनाए हुए हैं। कोई भी समझ सकता है, अगर दुनिया में शांति और खुशी है तो उनसे हथियार और हथियारों का जखीरा कौन खरीदेगा, इसलिए उनके डिफेंस प्रोडक्शन को बेचने और उससे प्रॉफिट कमाने के लिए यह ज़रूरी है कि युद्ध चलते रहें; अगर नॉर्मल तरीके से नहीं तो इनका इंतज़ाम किसी न किसी तरह से तो करना ही होगा। वे लोग दयनीय हैं जो उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के तरीकों में फंस गए और अपने जंगल को कंक्रीट के जंगल में, खेती के खेत को तथाकथित इंडस्ट्रियल पार्क में, होटलों और एयरपोर्ट को भारी कर्ज में बदल दिया, अपनी करेंसी और इज्जत को कम कर दिया। क्या ऐसी ताकत पर भारत मदद और सहयोग के लिए भरोसा कर सकता है?

A.7). सिर्फ़ इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के लिए इंडस्ट्रियलाइज़ेशन ने कई देशों को बर्बाद कर दिया है और इंसानों को उनके बेसिक कामों से दूर कर दिया है और उन्हें समाज के निचले तबके में बेरोज़गार और अकेला कर दिया है, जबकि बहुत ज़्यादा मशीनों ने समाज के ज़्यादा इनकम वाले तबके के लोगों को

अस्वस्थ, अपाहिज और क्वारंटीन कर दिया है। इससे पता चलता है कि मशीनों के इस्तेमाल को लेकर देश और समाज के लेवल पर कुछ बेसिक और पक्की हद तय करने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए, सभी पीसने, काटने, टुकड़े करने और उन्हें बांटने का काम मशीनों के लिए रोका जा सकता है। सिर्फ़ यही काम देश के लोगों को नौकरी/काम देने की समस्या को काफी हद तक हल कर देगा। भारत के लिए एगोफॉरेस्ट्री पर आधारित इकोनॉमिक मॉडल किसी भी दूसरे ऑप्शन की जगह बेहतर ऑप्शन कहा जा सकता है।

A.8). भारत ने अपने लंबे इतिहास में देखा है कि सोने की लंका जलाकर राख कर दी जाती है और सोने की चिड़ियों को बेरहमी से लूटा जाता है। भारत ने अपने लंबे इतिहास में सीखा है कि युद्ध के दौरान सबसे पहले इकॉनमी को नुकसान होता है, एनर्जी का सोर्स कमज़ोर हो जाता है और डेटा सेंटर नष्ट हो जाता है, इसलिए उम्मीद है कि भारत उन बातों में नहीं फंसेगा जो दुनिया का मीडिया फैला रहा है।

A.9). ऐसा लगता है कि सभी धर्मों ने अपनी अहमियत खो दी है (जो असल दुनिया में कोरोना-कोविड ने दिखाया है) और बुनियादी धर्म फिर से ज़िंदा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके अलावा कोरोना ने साबित कर दिया है कि दुनिया एक हो गई है और ऐसे में हिम्मत दिखाना और भी ज़रूरी होगा और आइए भारत को फिर से डिफाइन करें, इसकी सरकार, ज्यूडिशियरी, इनकम और टैक्स, सिक्योरिटी और सेफ्टी, एनर्जी और एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और हेल्थ को इस तरह से फिर से डिफाइन करें कि ये खुद को बनाए रख सकें और सिस्टम को हमेशा (सनातनता) दे सकें।

(B) प्रस्ताव का सारांश

बी.1)। हमारा देश – भारत एक ऐतिहासिक मोड़ पर है। एक्सपेरिमेंट और सेंट्रलाइज़ेशन के हाल के दौर ने सिस्टम में एक अंदरूनी स्ट्रक्चरल खालीपन दिखाया है, जो कुछ समय के लिए असरदार तो रहा, लेकिन लोगों की बड़ी उम्मीदों को पूरा करने या उन्हें बनाए रखने में नाकाम रहा है।

'धर्म के पुनरुत्थान' की ओर से हस्ताक्षर करने वाले ने सरकार के साथ मिलकर एक नया गवर्नेंस मॉडल डिज़ाइन करने और लागू करने का प्रस्ताव रखा है — ऐसा मॉडल जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को सभ्यता की समझ के साथ मिलाए। यह मॉडल, जो धर्म और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है, का मकसद लोगों का भरोसा, संस्थाओं में तालमेल और लंबे समय तक देश की स्थिरता वापस लाना है। हमारा मकसद पॉलिटिकल सर्वाइवल से सिविलाइज़ेशनल लीडरशिप की ओर बढ़ना है — भारत को आइडियोलॉजी पर नहीं, बल्कि वैल्यूज़ पर आधारित गवर्नेंस के एक मॉडल के तौर पर पेश करना; एथिक्स पर, न कि एक्सपीडिएंसी पर।

बी.2)। संगठनात्मक क्रेडेंशियल

'धर्म का पुनरुत्थान' एक सामाजिक-आर्थिक-धार्मिक-राजनीतिक संगठन है जो धर्म के पुनरुत्थान और धर्म संस्थान की स्थापना की दिशा में काम करता है और सरकारों को राष्ट्रीय और भू-राजनीतिक मुद्दों, शासन, संस्थागत सुधार और पॉलिसी इनोवेशन पर सलाह देता रहता है।

हमारी कोर टीम में शामिल हैं:

पॉलिसी आर्किटेक्ट और कल्चरल स्ट्रैटेजिस्ट जिन्हें ट्रेडिशनल गवर्नेंस एथिक्स को मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के साथ जोड़ने का अनुभव है, संत और साधु जो सनातन धर्म के सिद्धांतों पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं , एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का फिलॉसॉफिकल बेसिस जो सनातन (हमेशा) को बनाए रख सकता है, और गवर्नेंस और एग्जीक्यूटिव डिज़ाइन फ्रेमवर्क के अंदर उनका मॉडर्न अडैप्टेशन।

बी.3). सामरिक संदर्भ

देश में सरकार की उथल-पुथल सिर्फ राजनीतिक झगड़े से नहीं, बल्कि बुनियादी तालमेल की कमी से भी पैदा होती है। बाहर से आए राजनीतिक ढांचे — चुनावी लोकतंत्र, या लोकतांत्रिक तानाशाही — देश की सामाजिक और आध्यात्मिक ज़मीन से अपने आप नहीं बने हैं। **इस मतभेद का नतीजा यह हुआ है:**

- I. संस्थागत अस्थिरता और कमज़ोर पॉलिसी कंटिन्यूटी; एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट से लोगों का दूर होना; शासन में नैतिक वैधता का खत्म होना; और
- II. एक कॉमन वैल्यू फ्रेमवर्क के तहत लीडरशिप और नागरिकों को एकजुट करने वाले एक कॉमन नेशनल लोकाचार का अभाव,

इसका समाधान शासन को नैतिक संप्रभुता में फिर से स्थापित करने में है — एक ऐसा सिद्धांत जो कार्यकारी अधिकार को नैतिक और सांस्कृतिक वैधता के साथ जोड़ता है, यह सुनिश्चित करता है कि शासन कुशल और न्यायपूर्ण दोनों हो।

B. 4). प्रस्तावित रूपरेखा :

धर्म-केंद्रित शासन मॉडल (डीसीजीएम)

'धर्म का पुनरुत्थान' सरकार के साथ मिलकर एक धर्म-केंद्रित शासन मॉडल (DCGM) बनाने का प्रस्ताव करता है — जो शासन का एक संरचनात्मक रूप से आधुनिक लेकिन नैतिक रूप से पारंपरिक सिस्टम है, जिसमें तीन संस्थागत स्तंभ शामिल हैं:

एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी (राजनीति): एक रीस्ट्रक्चर्ड लीडरशिप और फैसले लेने का सिस्टम जो पावर के बजाय ड्यूटी (धर्म) पर आधारित हो।

एडवाइजरी काउंसिल (धर्म परिषद): एक नैतिक और बौद्धिक निगरानी करने वाली संस्था जो यह पक्का करती है कि सभी पॉलिसी राष्ट्रीय नैतिकता, सामाजिक न्याय और सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से हों।

एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म (कर्म मंडल): एक रिज़ल्ट-ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी जिसे एथिकल डिजीजन-मेकिंग, अकाउंटेबिलिटी और सिटिज़न सर्विस में ट्रेन किया गया हो।

ये पिलर मिलकर: ट्रांसपेरेंसी और सर्विस एथिक्स के ज़रिए जनता का भरोसा फिर से बनाएंगे; पॉलिटिकल साइकिल से आगे भी गवर्नेंस को जारी रखेंगे; टूटे-फूटे ग्लोबल ऑर्डर में देश को एक नैतिक और स्ट्रेटेजिक लीडर के तौर पर खड़ा करेंगे।

बी.5)। कार्यान्वयन रोडमैप

फेज़ ड्यूरेशन :: मुख्य डिलिवरेबल्स

फेज़ I : डायग्नोस्टिक और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट 3-4 महीने गवर्नेंस ऑडिट, स्टैकहोल्डर कंसल्टेशन, इंस्टीट्यूशनल मैपिंग

फेज़ II: फ्रेमवर्क डिज़ाइन और कॉन्स्ट्रक्शनल ड्राफ्टिंग 6-9 महीने ड्राफ्ट मॉडल चार्टर, इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, पायलट इम्प्लीमेंटेशन प्लान

फेज़ III: इंस्टीट्यूशनलाइज़ेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग 12-18 महीने ट्रेनिंग मॉड्यूल, पॉलिसी इंटीग्रेशन, इवैल्यूएशन और रिफाइनमेंट

हर फेज़ को लोकल एक्सपर्ट्स, नेशनल मिनिस्ट्रीज़ और कल्चरल लीडर्स के साथ मिलकर पूरा किया जाएगा ताकि ओनरशिप और घरेलू असलियत के साथ तालमेल पक्का हो सके।

बी.6)। भारत के लिए रणनीतिक लाभ

- I. जब शासन हमेशा चलने वाली नैतिक नींव पर टिका होता है, तो उसे नैतिक ताकत मिलती है। सिविलाइज़ेशनल लीडरशिप: देश 21वीं सदी में वैल्यू-बेस्ड शासन का पायनियर बनकर उभरता है।
- II. इकोनॉमिक और डिप्लोमैटिक रेजिलिएंस: स्टेबिलिटी और मोरल क्लैरिटी इन्वेस्टमेंट, कोऑपरेशन और सॉफ्ट पावर को पहचान दिलाती है। नेशनल कोहेशन: नागरिकों, इंस्टीट्यूशन और लीडरशिप के बीच मकसद की एक जैसी भावना।

III. यह सुधार न सिर्फ मौजूदा बदलाव को स्थिर करेगा, बल्कि शासन के एक नए युग की बौद्धिक नींव भी स्थापित करेगा — जो नैतिक, आत्मनिर्भर और दुनिया भर में सम्मानित होगा।

बी.7)। जुड़ाव और बिलिंग ढांचा

यह एंगेजमेंट भारत सरकार के ग्रुप 'रिसरेक्शन ऑफ़ धर्मा' के तहत एक मल्टी-स्टेज कंसल्टिंग पार्टनरशिप के तौर पर बनाया गया है, लेकिन जैसा कि पहले बताया गया है कि हम कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट नहीं हैं, इसलिए उम्मीद है कि भारत सरकार और समझदार नागरिक समझदारी से टीम मेंबर्स को कुछ मानदेय के साथ सभी सुविधाएं देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस प्रपोज़ल के एक्सेप्ट होने पर एक डिटेल्ड बजट नोट और पेमेंट शेड्यूल सबमिट करेंगे।

बी.8)। साझेदारी प्रस्ताव

'रिसरेक्शन ऑफ़ धर्म' एक जॉइंट गवर्नेंस रिफॉर्म टास्क फोर्स का प्रस्ताव करता है, जिसकी को-चेयर सरकार और 'रिसरेक्शन ऑफ़ धर्म' के रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, जो प्रोजेक्ट के डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन की देखरेख करेगा।

(C). आखिरी सबमिशन

गवर्नेंस में नई जान डालने का समय आ गया है — बाहर से लाए गए सिस्टम की असुरक्षा और अस्थिरता से खुद से बने सिस्टम के भरोसे की ओर बदलाव।

धार्मिक नैतिकता को मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के साथ मिलाकर, यह पार्टनरशिप एक स्थिर, सही और दूर की सोचने वाला गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने में मदद करेगी जो इस बदलते दौर में देश को रास्ता दिखा सके। इससे भारत के हर नागरिक और उसके असली मेहमानों को सोशल सिक्योरिटी (सभी युवाओं को खाना, पानी, कपड़ा, घर, शिक्षा, सेहत, न्याय, मनोरंजन और बेसिक नौकरी की फिजिकल सेफ्टी और सिक्योरिटी और सभी सीनियर सिटिज़न को इज्जतदार माहौल) मिलेगी, जिसे समाज और सरकार मिलकर मैनेज करेंगे। 'धर्म का पुनरुत्थान' ग्रुप इस जुड़ाव को शुरू करने के लिए तैयार है और बिहार और पूरे भारत के लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि वे आगे आएँ और हमारे देश इंडिया को फिर से एक हेल्दी, खुशहाल और पवित्र देश बनाने के लिए हमारे साथ काम करें।

ऊपर सबमिट किया गया है,

सादर

नरेंद्र अग्रवाल

धर्म के पुनरुत्थान के लिए,

वेबसाइट: resurrectionofdharma.com, तारीख: 06.11.2025, दिल्ली, भारत

बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर 2025: पार्ट- 2

विषय: 06.11.2025 के लेटर के अलावा “बिहार असेंबली इलेक्शन नवंबर 2025” पर सबमिशन, जिसमें परिवार, समाज और भारत सरकार के मैनेजमेंट सिस्टम को धर्म (बेसिक धर्म) के हिसाब से बदलने और धर्म संस्थानों (धार्मिक संस्थाओं) को फिर से बनाने की ज़रूरत है ताकि भारत के सभी नागरिकों और असली मेहमानों को सिस्टमैटिक और टाइम फ्रेम में पूरी सोशल सिक्योरिटी (यानी फिजिकल सेफ्टी, और हवा, खाना, पानी, कपड़ा, रहने की जगह, शिक्षा, हेल्थ, जस्टिस, एंटरटेनमेंट और नौकरी के मौके और क्रिएटिविटी दिखाने वगैरह) का ध्यान रखा जा सके। - बिहार और पूरे भारत के लोगों का टेंशन कम करने के लिए कंसल्टेंसी देने के लिए (खुद से) दिलचस्पी दिखाना, एक प्रैक्टिकल तरीका -- इस बारे में

CC: ज़रूरी कार्रवाई के अनुरोध के साथ पढ़ने के लिए,

1. महामहिम सुश्री द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति,
2. महामहिम श्री सी.पी. राधाकृष्णन, भारत के उपराष्ट्रपति
3. माननीय श्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री,
4. माननीय श्री ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष
5. माननीय श्री अमित शाह, गृह मंत्री,
6. माननीय श्री एस. जयशंकर, विदेश मंत्री
7. माननीय श्री सुमन बेरी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष,

भारत के सम्मानित साथी नागरिकों

06.11.2-25 की तारीख वाले सबमिशन के सिलसिले में, इस लेटर में ये बातें शामिल हैं: (A). बड़ी आउटलाइन, (B). अंतिम प्रस्तुतिकरण,

(ए) व्यापक रूपरेखा

पहले तीन पॉइंट्स (A.1 से A.1.3) को कुछ जोड़कर यहाँ दोहराया गया है और उसके बाद नया सबमिशन (पॉइंट A.2 से आगे) किया गया है, जो नीचे दिया गया है:

ए.1)। नीचे साइन करने वालों को नहीं लगता कि इस आर्टिकल ने 06.11 को हुई वोटिंग पर असर डाला है और आने वाली 11.11.2025 की वोटिंग पर भी किसी भी तरह से असर डालेगा, लेकिन उम्मीद है कि यह आर्टिकल बिहार के साथ-साथ पूरे देश में इस बात पर ज़रूर चर्चा शुरू करेगा कि देश और लोगों की तरक्की और विकास के लिए सभी 28 राज्यों में ऐसे चुनाव कराना और उन्हें बनाए रखना ज़रूरी है।

A.1.2). इंटेलेक्चुअल क्लास में इस बात पर चर्चा हो रही है कि: बिहार में असेंबली इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन एक नेगेटिव (ज़ीरो भी नहीं) गेम है, जहाँ बिहार के साथ-साथ भारत में भी हर कोई हारता है, चाहे कोई भी जीते और MLA बने और कौन सब मिलकर सरकार बनाए और मिनिस्टर या चीफ़ मिनिस्टर बने।

इसके अलावा इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव नेताओं का खुद को और अपने समर्थकों को बेवकूफ बनाने का एक खुद का जुनून है और यह बिहार के लोगों की कोशिश का एक और दौर है ताकि वे धोखा खाने, लूटने, बीमार होने और बेवकूफ बनने के बजाय कुछ सुकून पा सकें और फिर निराशा और लाचारी की भावना से घिरे रहें।

इसके अलावा, इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव एक कबाड़ के सौदागरों और चालाकी के उस्तादों की बिहार और पूरे भारत को कबाड़खाना और जानवरों की दुनिया में बदलने की होड़। बिहार और भारत और दुनिया की मौजूदा हालत का गहराई से एनालिसिस, साथ ही सुधार के लिए कंसल्टेंसी का ऑफर नीचे दिए गए पॉइंट्स में दिया गया है।

नोट: मेरे हिसाब से बिहार (और पूरे भारत में) में विधान सभा , विधान परिषद और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी किसी MLA, MLC, नगर निगम के प्रतिनिधि, पंचायत की कोई ज़रूरत नहीं है। हर चुनाव क्षेत्र से चुने हुए प्रतिनिधियों की एक छोटी टीम के साथ संसद के सदस्य इलाके को चलाने/मैनेज करने और सुविधा देने के लिए काफी हैं। [सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, अभी बिहार में हर व्यक्ति की सालाना कम से कम प्रति व्यक्ति आय लगभग 55000 हजार है, लेकिन अगर कोई इस इलाके में आज़ादी से घूमे, तो उसे बिहार में फैली 'बहुत ज़्यादा गरीबी और गंदी हालत' भी आसानी से दिख जाएगी, जिससे हर तरह की बीमारियाँ होती हैं [पटना और मशहूर IAS कॉलोनी (जहाँ मैं अपने अकेलेपन के दौरान काफी समय तक रहा हूँ) भी शामिल हैं]। बिहार में गंदी हालत खुद ही बताती है कि बिहार में डॉक्टरों को सबसे ज़्यादा दहेज मिलता है (IAS/IPS के बाद) जबकि नेताओं को शायद ही कोई दहेज मिलता है और मच्छर भगाने वाली दवाइयों, दवाओं की बिक्री किसी भी दूसरी चीज़ (चावल, गेहूं या दालें वगैरह) से ज़्यादा है।

A.1.2). नीचे साइन करने वाले, नरेंद्र अग्रवाल (उम्र 59 साल), ग्रुप (रिसरेक्शन ऑफ धर्म) के मुख्य व्यक्ति, भारत के असली निवासी हैं, जिनकी छोटी प्रोफाइल सोशल साइट LinkedIn/Facebook, हमारी वेबसाइट: **resurrectionofdharma.com** के ज़रिए देखी जा सकती है। इसके अलावा, वेबसाइट पर नीचे साइन करने वाले की प्रोफाइल भी दिखाई गई है। तैयारी इस दावे के पीछे फ्री में डाउनलोड होने वाली किताबों के ज़रिए सब्जेक्ट कंसल्टेंसी देने का दावा है, जो ओपन मार्केट में उपलब्ध नहीं हैं (किताबें हैं: “मीता-लाइफ़ स्टाइल एजेंडा, डिविक्नेसी (दिव्य लोकतंत्र), काम की बात और अल्टरनेट इकॉनमी” जिसमें देश और दुनिया के लिए बड़ा एजेंडा है) और उनमें दिए गए इंटरव्यू और पॉडकास्ट के लिंक के ज़रिए। इसके अलावा, तैयार रेफरेंस के लिए दो पॉडकास्ट के लिंक नीचे दिए गए हैं:

https://youtu.be/FD21cRfBmjs?si=w4wYpanTGR0fWiRH_,

और, https://youtu.be/-8H6j9mmY5M?si=eKI22EBfQlaNKzD5_,

इसके अलावा, नीचे साइन करने वाले को देश का अनुभव है और उन्होंने साल 2019 से दिसंबर 2024 तक पूरे देश में ट्रेवल किया और वहीं रहे, जबकि खास तौर पर बिहार और झारखंड रीजन में वे मार्च, 2019 से सितंबर 2019 तक (पटना, सीतामढ़ी, सासाराम और रांची में) और फिर जुलाई 2020 से जनवरी 2022 तक (पटना में) रहे और यहां दी गई जानकारी को एक फर्स्टहैंड एक्सपीरियंस माना जा सकता है, न कि किसी और की लिखी किताबों से सीखा हुआ चैप्टर।

नीचे साइन करने वाला यह भी बताना चाहता है कि यह कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट नहीं है और सब्जेक्ट कंसल्टेंसी का यह ऑफर कुछ जाने-माने संतों, साधु, साध्वी, एक्सपर्ट्स और मास्टर्स के कहने पर दिया जा रहा है ताकि हिमालय से लेकर भारत के मैदानों और हिंद महासागर तक हमारी सभ्यता की शान को वापस लाया जा सके, और पूरी दुनिया के इंसानों को प्रकृति के साथ रहने और हेल्दी, खुशहाल और पवित्र ज़िंदगी जीने के लिए गाइड किया जा सके।

A.1.3). जब किसी देश के लिए ब्रेन ड्रेन, मनी ड्रेन, फेवरिटीज्म और करप्शन जैसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगता है, तो इसका मतलब है कि देश में चेक और बैलेंस बनाए रखने वाले ज़रूरी इंस्टीट्यूशन बहुत पहले ही साइडलाइन हो चुके हैं और काम करना बंद कर चुके हैं।

यह देखा जा सकता है कि अगर देश के ज़रूरी इंस्टीट्यूशन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि देश की कलेक्टिव लीडरशिप (चाहे वे पावर में हों या अपोज़िशन में) या तो इनएफिशिएंट हैं या करप्ट हैं या दोनों (इनएफिशिएंसी या करप्शन में से एक अच्छाई दूसरे को जन्म देती है)।

अगर लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेटर, जज वगैरह में ये नाकामी और करप्शन के लक्षण कई इलेक्शन के बाद भी बने रहते हैं, तो यह पक्का है कि लीडरशिप चुनने या चुनने का प्रोसेस ही गलत हो जाएगा। यह बात बताती है कि यह टीचर और उनके मास्टर की गलती है और उनके पढ़ाने और समाज और देश को बनाने के तरीके की भी। अगर किसी देश के टीचर और मास्टर गलती करते दिख रहे हैं, तो यह पक्का है कि असली साधु-संत अपने एकांत में चले गए होंगे और चालाकी और नकली/गुप्त विद्या के मास्टर उस खाली या बची हुई जगह में घुस गए होंगे, जो उस इलाके की आध्यात्मिक समझ को चकमा देकर खुलेआम हंगामा करने के लिए काफी कही जा सकती है।

A.2). आध्यात्मिक दुनिया में कहा जाता है कि जैसे ही महाभारत खत्म हुआ, गांडीव (अर्जुन का धनुष और बाण) की ताकत भी खत्म हो गई, और जैसे ही भगवान कृष्ण चले गए, अंधेरा छाने लगा और डार्क-एज या ब्लैक-एज या कलयुग या मशीन-एज (काल-पुर्जा युग) या कलयुग या कल -कली का दौर शुरू हो गया। कलयुग की शुरुआत के साथ ही सभी ऋषियों ने अपने पैर पीछे कर लिए और खुद को एकांत और प्रार्थना में लगा लिया।

कहा जाता है कि डार्क एज के शुरू होते ही सभी नाइटी-आउल्स, बैटमैन, स्पाइडरमैन, शिकारी, लुटेरे, चोर, बहकाने वाली, जादूगर, डार्क वेब चलाने वाले, चालाक कलाओं, काले जादू और सूडो-साइंस के मास्टर, और दूसरे जीव और उपदेशक जो आम तौर पर अंधेरे में काम करते हैं, एक्टिव हो गए और अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर दीं।

आम लोग जो अंधेरे के असर में थे और जिन्हें संतों और महात्माओं से सही सुरक्षा और गाइडेंस नहीं मिली थी, वे आसानी से चालाक कलाओं और काले जादू के उस्तादों की तरफ खिंचे चले आते थे।

अंधकार युग का पहला असर तब दिखा जब लोग रोज़मर्रा की दुआओं से दूर, अंधकार युग से अंधे, सड़े हुए फलों और अनाज से बनी शराब के नशे में इतने बेपरवाह, बेइज़्जत और कमज़ोर हो गए कि वे बड़ों, पक्षियों और जानवरों, पेड़-पौधों, मछलियों और पानी के जीवों के प्रति इज़्जत और फ़र्ज़ नहीं निभा पाए, नतीजतन इनसे आपसी सहयोग छीन लिया गया और वे निराश हो गए।

निराश होकर लोग खुद को सुधारने के बजाय, ज़मीन से जुड़े रहे, पवित्रता को मानने और मूर्खता को ठुकराने के बजाय, अपने रोज़मर्रा के काम, खासकर खेती में सहयोग न करने की इस घटना को अपने तथाकथित दबदबे पर हमला समझ बैठे।

फिर संत के भेष में शैतान आता है जो लोगों को पालतू जानवरों को वश में करने, किसी भी तरह से पालतू जानवरों पर कंट्रोल करने की सलाह देता है, चाहे इसके लिए बछड़े को मारना पड़े या बैल को बधिया करना पड़े, उनकी नाक छिदवाकर उसमें धागा/रस्सी डालनी पड़े, बागियों पर हमेशा वज़न डालकर उन्हें कैद और कैद में रखना पड़े। दोस्तों के भेष में ये दुश्मन लोगों को आगे सलाह देते हैं कि इन्हें एक काम की चीज़ की तरह इस्तेमाल करें और इनका पूरा इस्तेमाल करें। संतों के भेष में ये शैतान, दोस्तों के भेष में दुश्मन लोगों को आगे सलाह देते हैं कि जानवर और सोना अपने पास रखना ताकत की निशानी है, अपने फायदे के लिए माहौल का इस्तेमाल करना चाहिए, और जिसके पास ये ज़्यादा होंगे, वही ताकतवर होगा। इन सबने लोगों की सोच और उसके बाद के व्यवहार और काम में एक बड़ा बदलाव लाया है।

अपने फ़ायदे के लिए पर्यावरण का इस्तेमाल करने के इस विचार ने जानवरों, खासकर गायों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं। बैलों को बधिया करके इन्हें बैल बनाना और खेती में गुलाम जानवरों की तरह इस्तेमाल करना, हमारे खाने और पीने वाले पूरे दूध में बैल और गाय का श्राप ले आया है। इसे सबसे बड़ी हैरानी की बात कहा जा सकता है कि कैसे पूरी कम्युनिटी यह बेसिक बात भूल गई कि "यह खाना/दूध है जो मूड तय करता है और पानी जो आवाज़ तय करता है" और खुद को सबसे नीचे गिरा दिया/डाउनग्रेड कर लिया, वह भी भारत जैसे देशों में जो दावा करता है कि उसके आंगन में सबसे बड़ी और सबसे बड़ी समझदारी है। यह और भी हैरानी की बात है कि पिछले तीन हज़ार सालों में ज़्यादातर नए धर्म, जो इंसानी सोच को ऊपर उठाने की बात करते हैं, इस बहुत बेसिक मुद्दे पर चुप रहे कि ट्रिंक एंड डाइन, जो पूरे इंसानी मन और उसके डायनामिक्स को बदल देता है। अफ़सोस!

भारत के लिए गायों के प्रति यह फ़ायदेमंद व्यवहार इसलिए और भी हैरानी की बात है क्योंकि इसके ज़्यादातर लोग शिव के मंदिरों में नंदी (बैल) और गाय को माता मानते हैं। इसके अलावा, यह समझना भी बहुत अजीब लगता है कि गायों के प्रति असल ज़िंदगी में होने वाले इस जुल्म और क्रूरता को बहुत सारे पंडित, संत और साधु कैसे नज़रअंदाज़ कर देते हैं जो गायों और भगवान शिव और उनके दरबारियों के बारे में बोलते और मंत्रोच्चार करते रहते हैं। ऐसे उपदेशकों का अनादर, ऐसे समुदायों का गरीबी में रहना और ऐसे देशों की गुलामी, गायों के प्रति बुरे बर्ताव के स्वाभाविक नतीजे हैं।

जो लोग गाय का दूध पी रहे हैं और फिर बीफ़ खा रहे हैं, उनके बारे में कहा जा सकता है कि वे मशीनों की तरह बेपरवाह हो गए हैं और कहीं न कहीं उन्होंने खुद को मशीनों की तरह इस्तेमाल होने के लिए सरेंडर कर दिया है और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए अगर ये भाईचारे और नरसंहार की ओर मुड़ जाएं।

गर्म रेगिस्तान या बर्फीले ठंडे माहौल वाले देशों में बीफ़ की बढ़ती खपत ने इन्हें भारत जैसे देशों में डेयरी बिज़नेस बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। इसके लिए वे सॉफ्ट लोन और दूसरी प्रमोशनल स्कीमें दे

रहे हैं ताकि डेयरी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल हो सके, ताकि बीफ़ की लगातार मांग पूरी हो सके। इसका नतीजा यह है कि दूध और चीनी वाली चाय और कॉफ़ी की खपत बढ़ गई है। इससे समस्या और बढ़ गई है और गायों के खिलाफ़ अपराध बढ़ गए हैं। इसके अलावा, सबसे उपजाऊ ज़मीन का 25 से 30 परसेंट हिस्सा घास, गन्ना, चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए इस्तेमाल होने लगा है, जिसे जंगलों की कटाई और उसके बाद क्लाइमेट चेंज और हर तरफ़ दुख का एक बड़ा कारण कहा जा सकता है।

A.2.1). अफ़सोस! साधु-साध्वी, सुखी गुरु और सद्गुरु की पूरी नस्ल भी जानवरों पर जुर्म करके इकट्ठा किया गया दूध पीकर इतनी खराब हो गई है कि समाज में उनकी कोई चलती नहीं। ज़्यादा दूध के क्रेज़ ने बच्चों को इतनी कम उम्र से खराब कर दिया है कि जब वे बड़े होते हैं तो उन्हें यह (बछड़ों को उनकी माँ का दूध पीने से रोकना, नर बच्चों को मारना और बधिया करना) जुर्म नहीं लगता और यहाँ तक कि जो लोग गाय माता और ताकतवर नंदी की तारीफ़ में नारे लगाते रहते हैं, उन्हें भी कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता।

यह कहा जा सकता है कि साधु, साध्वी, स्वामी, सन्यासी, संन्यासिन जैसे लोगों को खुद को शुद्ध करने, गहरे ध्यान और बड़े यज्ञ (निस्वार्थ काम) की ज़रूरत होती है, जिसमें सभी आराम को छोड़ दिया जाता है। यह उनका खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास वापस लाने और लोगों का नेतृत्व करने और नाम रोशन करने के लिए फिर से हकदार बनने का पहला ज़रूरी कदम है।

आइए, भगवान से प्रार्थना करें कि हमें इतनी समझ और समझ दें कि हम गाय और बैल के साथ और अपराध करने से खुद को रोक सकें, और इतनी ताकत दें कि हम सभी जीवित और निर्जीव प्राणियों का सम्मान वापस ला सकें और अपनी सभ्यता की शान को फिर से ज़िंदा कर सकें।

A.3). जब मैं बिहार से लगभग दो साल अकेलेपन में (मार्च 2019 से जनवरी 2022 के बीच) बाहर आ रहा था, तो एक प्रोफेसर और बिहार सरकार के चीफ़ एडवाइजर ने एक कर्टसी मीटिंग में मुझसे पूछा, “आपने बिहार में ऐसा क्या देखा है, जो बिहार के लिए खास हो, और इसके अतीत और वर्तमान के बारे में आपकी क्या राय है और इसके भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं?” इस सवाल के जवाब में मैंने जो बातें उन्हें बताईं, वे नीचे इस तरह हैं: यह सवाल मैंने खुद बिहार में हजारों लोगों से पूछा था और मुझे जवाब मिला:

सवाल: i). बिहार की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? ii). बिहार की सबसे बड़ी ताकत क्या है? iii). अगर बिहार नीचे गया है तो इसके लिए किसे ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है और अगर बिहार को फिर से ऊपर उठना है तो लीड कौन करेगा?

जवाब: हैरानी की बात है कि ऊपर दिए गए तीनों सब-सवालों के जवाब में सभी ने (जिनमें शामिल हैं: आम आदमी, अकैडमिशियन, ब्यूरोक्रेट, पब्लिक सर्वेंट, दुकानदार, बिज़नेसमैन, पुजारी और पॉलिटिशियन), सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया: 'बिहारी', यानी हम खुद बिहारी हैं।

सवाल: अगर किसी इलाके की ज्योग्राफी समतल और उपजाऊ है, जहाँ खूब पानी है और साल भर धूप आती है और जहाँ के लोग भी मेहनती (मेहनती, मेहनती, पढ़ने वाले, मेहनती वगैरह) हैं, तो वह इलाका कैसा होना चाहिए और वहाँ रहने वाले लोगों की हालत कैसी होनी चाहिए?

उत्तर: यह एक बहुत विकसित समाज होना चाहिए जिसके आस-पास एक बड़ा जंगल हो और जिसके खजाने में हर तरह की दौलत हो।

सवाल: आपको कैसा लगता है जब एक ओपन सोर्स भी बिहार और बंगाल में इन बड़ी समस्याओं की ओर इशारा करता है? नीचे अठारह सबसे बड़ी समस्याएं दी गई हैं जिन्हें बड़े पैमाने पर बताया जा रहा है:

1. उच्च बेरोजगारी दर
 2. गरीबी और प्रति व्यक्ति कम आय
 3. कृषि संकट 4. बार-बार बाढ़ और सूखा
 5. खराब बुनियादी ढांचा विकास
 6. कम औद्योगीकरण
 7. भ्रष्टाचार और नौकरशाही की अक्षमता
 8. कमज़ोर हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर
 9. कम साक्षरता और शिक्षा की गुणवत्ता
 10. कुशल युवाओं का पलायन
 11. खराब कानून और व्यवस्था,
 12. कमज़ोर गवर्नेंस और इम्प्लीमेंटेशन में कमी
 13. जनसंख्या दबाव,
 14. जाति आधारित समाज, सामाजिक असमानता और उसकी राजनीति,
 15. अपर्याप्त स्वच्छता और स्वच्छ जल की पहुंच,
 16. लैंगिक समानता का अभाव, 16.
 17. पर्यावरण क्षरण
 18. **सबसे बड़ी समस्या:** ज़्यादातर लोगों का संस्थाओं, नेताओं पर से भरोसा उठ गया है और वे निराशा और लाचारी महसूस कर रहे हैं, जिससे वे ताना मारने वाले, टालमटोल करने वाले वगैरह हो गए हैं।
- ऊपर दी गई बात पर आपकी क्या राय है?**

उत्तर: वे, आध्यात्मिक लोगों का कहना है कि बिहार और बंगाल की ज़मीनी हकीकत, जहाँ सेहतमंद, खुश और पवित्र रहने के लिए ज़रूरी सभी तरह के साधन मौजूद हैं, किसी का छिपा हुआ श्राप लगता है जिसे हम आगे बढ़ा रहे हैं, या मृगतृष्णा, असंख्य या माया का असर है, वरना ऐसा माहौल (यानी एक ऐसा इलाका जहाँ हर तरह की समस्याएँ इतनी ज़्यादा हों कि बिहारी-बंगाली नाम भी समस्या, मज़ाक, गाली वगैरह का पर्याय बन जाए) इतने लंबे समय तक कामयाब नहीं हो पाता।

आध्यात्मिक लोगों का कहना है कि सुबह होने वाली है और यह बिहार-बंगाल और पूरे भारत के लोगों के लिए प्रार्थना और खुद को सुधारने का समय है। यह हमारे लिए अपने खाने, पानी, पीने की चीज़ों, कामोद्दीपक, कपड़ों, रहने की जगह और खुद के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ, समाज में और जिस तरह से हम अपना मनोरंजन करते हैं, उसमें सुधार करने का भी समय है। वे कहते हैं कि यह समय है कि हम प्रकृति के प्रति अपने व्यवहार में सुधार करें और बड़े मंथन के लिए तैयार हो जाएं जो तब होगा जब हम खुद को सुधारना शुरू करेंगे ताकि सभी बेवकूफी को नकारा जा सके और सभी कीमती चीज़ों को अपनाया जा सके।

बी)। समापन प्रस्तुति

गवर्नेंस में नई जान डालने का समय आ गया है — बाहर से लाए गए सिस्टम की असुरक्षा और अस्थिरता से खुद से बने सिस्टम के भरोसे की ओर बदलाव।

ऊपर बताई गई समझ के साथ, नीचे साइन करने वाले ने ग्रुप 'रिसरेक्शन ऑफ़ धर्मा' और भारत सरकार के साथ पार्टनरशिप का प्रस्ताव रखा है और यह पक्का किया है कि इससे एक स्टेबल, लेजीटिमेट और विज़नरी गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने में मदद मिलेगी जो बिहार और पूरे भारत को उसकी शान वापस लाने में गाइड कर सके।

'धर्म का पुनरुत्थान' ग्रुप भारत सरकार के साथ बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है और बिहार और पूरे भारत के लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि वे आगे आएँ और मिलकर काम करें ताकि इंडिया जो कि भारत है, उसे एक बार फिर से एक हेल्दी, खुशहाल और पवित्र देश बनाया जा सके - “मालिक गर्व और पड़ोसी मार्गदर्शक”।

ऊपर सबमिट किया गया है,

सादर

नरेंद्र अग्रवाल

धर्म के पुनरुत्थान के लिए,

वेबसाइट: resurrectionofdharma.com, तारीख: 08.11.2025, दिल्ली, भारत

बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर 2025: पार्ट- 2

भाग-3, बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर 2025:

विषय: “बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर 2025” पर दिनांक 06.11.और 08.11.2025 के पत्रों के अतिरिक्त प्रस्तुतियाँ, बिहार के साथ-साथ पूरे भारत की शासन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता और तदनुसार यह प्रस्तुति (इस खुले सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से) “बिहार के साथ-साथ पूरे भारत में शासन की संपूर्ण प्रणाली (धर्म के मूल सिद्धांतों के अनुसार) में सुधार के लिए परामर्श कार्य (स्वतः) की पेशकश करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति ताकि भारत के सभी नागरिकों और वास्तविक मेहमानों के लिए व्यवस्थित तरीके से पूर्ण सामाजिक सुरक्षा (अर्थात शारीरिक सुरक्षा, और हवा, भोजन, पानी, कपड़ा, आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, मनोरंजन और रोजगार के अवसर और रचनात्मकता की अभिव्यक्ति आदि की सुरक्षा) का प्रावधान सुनिश्चित किया जा सके” के संबंध में

- CC:** 1. महामहिम सुश्री द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति,
2. महामहिम श्री सी.पी. राधाकृष्णन, भारत के उपराष्ट्रपति
3. माननीय श्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री,
4. माननीय श्री ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष
5. माननीय श्री अमित शाह, गृह मंत्री,
6. माननीय श्री एस. जयशंकर, विदेश मंत्री
7. माननीय श्री सुमन बेरी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष,

भारत के सम्मानित साथी नागरिकों

06.11 और 08.11.2025 की तारीखों के सबमिशन के सिलसिले में, इस लेटर में ये सबमिशन शामिल हैं: (A). ब्रॉड आउटलाइन (B). अंतिम प्रस्तुतिकरण,

(ए) व्यापक रूपरेखा

A.1). सबसे पहले यह कहा जा सकता है कि नीचे साइन करने वाले किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठने की कोई इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन मैं पक्के तौर पर यह कह सकता हूँ कि यहाँ दिए गए एजेंडा को लागू करना (और इसलिए फ्री बेसिस पर कंसल्टेंसी का ऑफर) बिहार और पूरे भारत के लिए खुद को बचाने और आने वाले दिनों में दुनिया में देश के लोगों को गाइड करने का एकमात्र ऑप्शन है। पूरे ऑफर को मना करना/इग्नोर करना या सबमिशन के साथ छेड़छाड़ करना बिहार और पूरे भारत को दुनिया के तथाकथित खुद को मालिक कहने वालों के पैरों में सरेंडर करने और खत्म करने पर मजबूर

कर देगा, भले ही बिहार और पूरे भारत का मौजूदा लीडरशिप (पावर में हो या अपोज़िशन में) खुद को स्मार्ट/इंटेलिजेंट या भगवान का भेजा हुआ कैरेक्टर क्यों न कहे।

यह सबमिशन जनवरी 2003 (यानी पिछले बाईस साल से ज़्यादा) से राजनीतिक और उससे जुड़े सामाजिक-आर्थिक और धार्मिक घटनाक्रमों को ध्यान से और करीब से देखने का नतीजा कहा जा सकता है, जिसमें नीचे साइन करने वाले बिहार, भारत और पूरी दुनिया की ज़मीनी हकीकत को बेहतर बनाने के लिए आखिरी उपाय के तौर पर ऐसा करने पर मजबूर महसूस करते हैं ताकि हम इन हमलों से बच सकें और बिहार (पूरे भारत) और अपनी सभ्यता की शान को वापस ला सकें। इसके अलावा, यह सबमिशन सभी तरह के राजनीतिक नेताओं (राजा और राजा बनाने वालों और तथाकथित राजा बनाने वालों के पीछे के लोगों यानी राजा बनाने वालों के बनाने वालों) से अच्छी तरह बातचीत करने, एजेंडा और उसके तरीकों को डॉक्यूमेंट करने, गुरुओं, संतों और साधुओं/साध्वियों, बुजुर्गों और युवा पीढ़ियों (तथाकथित ज़ेन-ज़ेड) से फीडबैक लेने और हाल के बिहार विधानसभा चुनाव-2025 में घटनाक्रम और इवेंट मैनेजमेंट को देखने के बाद ही किया गया है।

A.2). नीचे साइन करने वाले यह बताना चाहते हैं कि 06.11 और 08.11.2025 के आर्टिकल बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग पर असर डालने के लिए नहीं बनाए गए थे और नतीजे बताते हैं कि इन आर्टिकल का चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ा है। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि बिहार में विधानसभा चुनाव कुल मिलाकर नेगेटिव गेम है (ज़ीरो भी नहीं), जहाँ बिहार के साथ-साथ भारत में भी हर कोई हारता है, चाहे कोई भी जीते और MLA बने और कौन मिलकर सरकार बनाए और कौन मंत्री या मुख्यमंत्री बने।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि बिहार (और भारत के दूसरे सभी राज्यों में भी) में असंबली चुनाव नेताओं का एक खुद का जुनून है ताकि वे किसी न किसी बहाने कई विदेशी ताकतों से बेवकूफ बनते रहें, धोखा खाते रहें, लूटते रहें, और उगाही करते रहें। वे कहते हैं कि बिहार (और पूरे भारत में) विधानसभा चुनाव एक कबाड़ के सौदागरों और चालाक कला के उस्तादों की दौड़ बिहार और पूरे भारत को कबाड़खाना और जानवरों के साम्राज्य में बदलने की है।

हमारे लिए विधान सभा , विधान परिषद और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी बिहार में (और पूरे भारत में भी) किसी MLA, MLC, नगर प्रतिनिधि, पंचायत की कोई ज़रूरत नहीं है।

A.3). बिहार, भारत और दुनिया की मौजूदा स्थिति को दिखाने के लिए, ओपन सोर्स (गूगल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का ज़िक्र किया जा रहा है और इन सोर्स से मिली जानकारी को पॉइंट नंबर A.9 पर हमारे नोट के साथ दोबारा पेश किया गया है (यानी पॉइंट नंबर: A.9.1, A.9.2 और A.9.3) ।

किसी को हैरानी हो सकती है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इतने खुले तौर पर दिखाने के बाद भी लोग और उनके लीडर (धार्मिक और पॉलिटिकल) या तो बेफिक्र, अनजान, खुद में डूबे, घमंडी और इसलिए बेवकूफ पाए जाते हैं या उनके पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता और इसलिए उनके पास खाने, पीने, सिगरेट पीने, प्रवचन देने और टाइम पास करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता।

इसके अलावा, आश्चर्य की बात है कि जब कोई गूगल-एआई से पूछता है कि, “बिहार, भारत और सामूहिक रूप से दुनिया जिस समस्या का सामना कर रही है, उसका समाधान क्या है, तो गूगल चकाचौंध हो जाता है और इस प्रश्न का उत्तर देने में एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) की पूरी श्रेष्ठता फीकी पड़ जाती है।

A.3.1). इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि अब तक हमें एक भी ऐसी प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फर्म नहीं मिली जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ज्यादातर लोग भारतीय हों या कह सकते हैं कि जिन्हें “धर्म, अर्थ, काम, राजनीति, राज्य और मोक्ष के भारतीय नज़रिए” की बेसिक समझ हो , जबकि वे सॉल्यूशन दे रहे हों, जबकि भारत में बहुत सारी कंसल्टेंसी फर्म हैं जो काम कर रही हैं और सभी राज्यों की सरकारों, नीति आयोग और भारत सरकार को सलाह दे रही हैं, जैसे: मैकिन्से, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG), और बेन एंड कंपनी, डेलॉइट, PwC, EY, और KPMG)।

A.4). 06.11 और 08.11.2025 की तारीख वाले लेटर को बिहार और पूरे भारत के गवर्नेंस सिस्टम को बदलने के लिए एक सही ऑफर (हालांकि सू मोटो) माना जाना था ताकि बिहार और पूरे भारत के सभी नागरिकों को पूरी सोशल सिक्योरिटी (यानी फिजिकल सेफ्टी, और हवा, खाना, पानी, कपड़ा, घर, शिक्षा, हेल्थ, जस्टिस, एंटरटेनमेंट और नौकरी के मौके और क्रिएटिविटी दिखाने वगैरह की सिक्योरिटी) एक सिस्टमैटिक और टाइम फ्रेम तरीके से मिले, लेकिन हमें अभी तक कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है। यह भारत के साथी नागरिकों, भारत की महामहिम और एड्रेस लिस्ट में दूसरे माननीय लोगों की जानकारी के लिए है। इसके अलावा, यह नया सबमिशन प्रपोज़ल को तेज़ करने और इस बारे में कुछ और पॉइंट्स भी सबमिट करने के लिए किया गया है, जिन्हें पढ़ने लायक माना गया है। इसके अलावा, अगर मांगा जाए तो इस लेटर और पिछले लेटर्स की हार्ड कॉपी भी जमा की जा सकती है।

A.5). पिछले ज़माने में बिहार में क्या हुआ और इस ज़माने के पिछले तीन हज़ार साल (जिसे कलयुग कहते हैं) में क्या हुआ, इसकी ज़्यादा डिटेल में जाए बिना, यह साफ़ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से बिहार (और इस मामले में भारत में भी) में घटनाएँ हुईं, बिहार ने इतने नखरे, उथल-पुथल और उथल-पुथल देखे हैं जितने किसी और इलाके में नहीं देखे गए। और इस तरह बिहार (भारत) इतना काबिल बना कि वह परिवार, समाज और देश को चलाने और मैनेज करने के तरीके में ज़रूरी बदलावों के बारे में सोच सके, प्लान बना सके और उन्हें लागू कर सके। और अपने नागरिकों को एक ऐसा प्लैटफ़ॉर्म दे सके जहाँ वे एक हेल्दी, खुश और पवित्र ज़िंदगी जी सकें और दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकें, ताकि वे भी वैसा ही करें और जो लय मिलेगी उसका मज़ा लें।

यहां, यह ध्यान देने वाली बात है कि हालांकि श्रीलंका, बांग्लादेश और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई दूसरे देश भी ऐसा ही बदलाव देख रहे हैं, लेकिन उन्हें यहां बताए जा रहे बदलाव को एक्सपेरिमेंट करने के लिए सही देश नहीं माना जा सकता, क्योंकि इन देशों में रहने वाले ज़्यादातर लोग धर्म और उसके परपेच्युटी (बेसिक धर्म जिसे संस्कृत में धर्म सनातन कहते हैं) और उसके अधिकारों, ज़िम्मेदारी और इनकम/यील्ड/रिसोर्स के बंटवारे के सिस्टम से भटक गए हैं, जिसकी यादें बिहार (भारत) खुशकिस्मत है कि आज भी बनाए हुए है।

इस निराशा से बाहर निकलने के लिए, बिहार (भारत) में असल में धर्म को फिर से ज़िंदा करने और धर्म संस्थान बनाने , बुरी ताकतों को खत्म करने और सही/संत ताकतों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐतिहासिक रूप से, यहाँ (सीतामढ़ी, बिहार-भारत) की माता सीता (सीता-राम) एक मिसाल हैं जिन्होंने रावण के आतंक के राज को खत्म किया था और कहा जा सकता है कि वे बहुत चर्चित राम राज्य को बनाने में पार्टनर थीं।

आध्यात्मिक दुनिया के जानकारों और लोगों का कहना है कि दुनिया के अभी के हालात रावण के राज जैसे हैं और आने वाले दिनों में भी ऐसा ही होगा, जिससे राम-राज्य की स्थापना होगी। इन जानकारों का कहना है कि श्रीलंका में राज व्यवस्था पहले ही भारत के अनुकूल हो चुकी है और अब भारत और पूरी दुनिया में बदलाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। [यहां यह भी बताना ज़रूरी है कि अगर कोई अकेले में सीतामढ़ी (भारत) और नेपाल (जनकपुर) के आस-पास के इलाके में जाए तो उसे लगेगा कि आने वाले दिनों में यह इलाका एक बार फिर दुनिया में सबसे आगे रहेगा और सनातन धर्म के अनुसार राज व्यवस्था स्थापित करेगा।]

A.6). बिहार एक मैदानी और उपजाऊ इलाका है जहाँ हिमालयी इलाके (गंगा, कोसी और गंडक नदी) के साथ-साथ अमरकंटक इलाके (सोन नदी) से भी काफ़ी बारिश होती है और पानी का बड़ा फ़्लो होता

है, जो कि बड़े पेड़ों और घने जंगल के लिए ज़रूरत से कहीं ज्यादा है, जो पूरे भारत की अलग-अलग जंगल की पैदावार और एनर्जी के लिए लकड़ी की बड़ी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। जब छत पर और शहरी खेती उपलब्ध है, तो बिहार में नॉर्मल खेती (ऑर्गेनिक या कोई और) करना बड़े ज्योग्राफिकल रिसोर्स की सरासर बर्बादी है और इसे ग्लोबल वार्मिंग के बुरे असर को कम करने या उसका मुकाबला करने में असहयोग कहा जा सकता है।

A.7). टूरिज्म और रेमिटेंस पर आधारित इकॉनमी हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेगी, और यह कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकती। टूरिज्म और रेमिटेंस पर आधारित इकॉनमी एक बुरा आइडिया है और इसमें गलती होने का पक्का तरीका है, चाहे वह श्रीनगर या स्विट्जरलैंड में प्लेज़र टूरिज्म हो, या धार्मिक टूरिज्म हो या एजुकेशनल और मेडिकल टूरिज्म हो, बम ब्लास्ट, किडनैपिंग, गलत व्यवहार और बीमारियों का फैलना कभी भी इन सोर्स से होने वाली इनकम पर आधारित पूरी इकॉनमी को खत्म कर सकता है।

टूरिस्ट से होने वाली इनकम और पैसे पर निर्भर रहना चर्च के पादरियों, मस्जिदों के मौलवियों और इन जगहों के बाहर बैठे भिखारियों के लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन समाज और देश के लिए नहीं। पैसे, धर्म, शिक्षा, हेल्थ/मेडिकल पर आधारित कोई भी टूरिज्म डेवलपमेंट एक दिखावटी समाज और देश बनाएगा और लोकल लोगों में (कम या ज्यादा) कॉम्प्लेक्स पैदा करेगा और भीख मांगने और फ्लैश ट्रेड को बढ़ावा दे सकता है या आकर्षित कर सकता है, इसलिए बिहार और भारत को इससे बचना चाहिए।

ऐसा लगता है कि सभी धर्मों ने अपनी अहमियत खो दी है (जो इस दुनिया में कोरोना-कोविड ने दिखाया है) और बुनियादी धर्म फिर से ज़िंदा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके अलावा कोरोना ने साबित कर दिया है कि दुनिया एक हो गई है और ऐसे में हिम्मत दिखाना और भी ज़रूरी होगा और बिहार (भारत) को फिर से परिभाषित करें, इसकी सरकार, न्यायपालिका, इनकम और टैक्स, सुरक्षा और सेफ्टी, एनर्जी और मनोरंजन, शिक्षा और स्वास्थ्य को इस तरह से फिर से परिभाषित करें कि ये सब खुद को बनाए रख सकें और सिस्टम को हमेशा (सनातनता) दे सकें।

ए.8)। सिर्फ़ इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के लिए इंडस्ट्रियलाइज़ेशन ने कई देशों को बर्बाद कर दिया है और इंसानों को उनके बेसिक कामों से दूर कर दिया है और उन्हें समाज के निचले तबके में बेरोज़गार और अकेला कर दिया है, जबकि बहुत ज्यादा मशीनों ने समाज के ऊँचे इनकम वाले तबके के लोगों को अस्वस्थ, अपाहिज और क्वारंटीन कर दिया है। इससे पता चलता है कि मशीनों के इस्तेमाल को लेकर देश और समाज के लेवल पर कुछ बेसिक और पक्की हद तय करने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए, सारी पीसने, काटने, टुकड़े करने और उसे बाँटने का काम मशीनों के लिए रोका जा सकता है। सिर्फ़ यही

काम देश के लोगों को नौकरी/काम देने की समस्या को काफी हद तक हल कर देगा। बिहार (और पूरे भारत में भी) के लिए एगोफॉरेस्ट्री पर आधारित इकोनॉमिक मॉडल किसी भी दूसरे ऑप्शन के बजाय बेहतर ऑप्शन कहा जा सकता है।

A.9). बिहार, भारत और दुनिया की मुख्य समस्याएँ क्या हैं?

A.9.1). बिहार की मुख्य समस्याएँ क्या हैं (ओपन सोर्स - गूगल, AI के अनुसार):

बिहार की मुख्य समस्याओं में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और हेल्थकेयर का बहुत कम विकास शामिल है , जिससे बेरोज़गारी और गरीबी बहुत ज़्यादा है। राज्य खेती पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, जो ज़्यादातर बेकार है, जबकि इसका इंडस्ट्रियल सेक्टर कमज़ोर बना हुआ है। दूसरी बड़ी समस्याएँ खराब डिज़ास्टर मैनेजमेंट हैं, खासकर बाढ़ के मामले में, और भ्रष्टाचार और जेंडर इनइक्वालिटी के मुद्दे हैं।

आर्थिक और रोज़गार चुनौतियाँ

- **खेती पर बहुत ज़्यादा निर्भरता:** खेती में 70% से ज़्यादा वर्कफ़ोर्स काम करता है, लेकिन राज्य की GDP में इसका हिस्सा 20% से भी कम है, जो पुराने तरीकों और स्किल्ड ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट की कमी के कारण कम प्रोडक्टिविटी दिखाता है।
- **कम इंडस्ट्रियलाइज़ेशन:** इंडस्ट्रियल सेक्टर का विकास ठीक से नहीं हुआ है, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, भरोसेमंद बिजली न होना और ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों की वजह से रुकावट आ रही है।
- **ज़्यादा बेरोज़गारी:** बिहार ज़रूरी लेबर मार्केट इंडिकेटर्स में दूसरे भारतीय राज्यों से पीछे है, और यहाँ नौकरी बनाने में काफ़ी दिक्कत है।

बुनियादी ढांचा और सामाजिक मुद्दे

- **इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी:** सड़कें, रेलवे, बिजली और हेल्थ सुविधाएं ठीक से डेवलप नहीं हैं, जिससे कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ में रुकावट आ रही है। हाल ही में हुई भारी बारिश ने सरकारी इमारतों और सड़कों की कमज़ोरी को सामने ला दिया है।
- **खराब एजुकेशन सिस्टम:** एजुकेशन सिस्टम में रिसोर्स की कमी, अनट्रेंड टीचर और ज़्यादा ड्रॉपआउट रेट जैसी चुनौतियाँ हैं। जेंडर में भी अंतर है, जिसमें लड़कियों की स्कूल अटेंडेंस कम है।
- **हेल्थकेयर की कमी:** राज्य को अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ज़्यादा मैटरनल मॉर्टलिटी रेट और कुपोषण जैसी समस्याएं हो रही हैं।

- **बाढ़ और आपदा मैनेजमेंट:** उत्तरी बिहार में बार-बार आने वाली मानसून की बाढ़ से परिवार बेघर हो जाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है, और आपदा से निपटने के लिए और ज़्यादा प्रोएक्टिव उपायों की ज़रूरत है।

शासन और सामाजिक मुद्दे

- **भ्रष्टाचार:** भ्रष्टाचार लोगों की भावनाओं पर असर डालने और विकास में रुकावट डालने वाला एक बड़ा कारण बना हुआ है।
- **गरीबी:** बिहार में शहरी और ग्रामीण इलाकों में गरीबी की दर बहुत ज़्यादा है, जो बेरोज़गारी और मौकों की कमी से और बढ़ जाती है।
- **जेंडर इनइक्वालिटी:** द हिंदू के अनुसार, महिलाओं में कम पढ़ाई-लिखाई, बाल विवाह और वर्कफोर्स में महिलाओं की कम हिस्सेदारी जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- **खर्च में गड़बड़ी:** बिहार में खर्च होने वाले पैसे का एक बड़ा हिस्सा राज्य से बाहर चला जाता है, जिससे राज्य की आर्थिक आत्मनिर्भरता कमज़ोर हो जाती है।

टिप्पणी:

- i). सरकारी कर्मचारियों, छोटे व्यापारियों, उनके परिवार वालों द्वारा जनता का शोषण, साथ ही छोटे साहूकारों और माइक्रो-फाइनेंस कंपनियों के बाउंसरों का कहर बिहार के लोगों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहा है।
- ii). यह कहा गया है कि अगर महामहिम को लगता है कि रेस्टोरेशन का काम बिहार से भी शुरू किया जा सकता है और फिर इसे पूरे भारत में आगे बढ़ाया जा सकता है, तो भारत सरकार DFID या USAID जैसी एजेंसियों को खोलकर दुनिया भर में सुधार शुरू कर सकती है।

A.9.2). भारत की मुख्य समस्याएं क्या हैं (ओपन सोर्स - गूगल, AI के अनुसार):

भारत की मुख्य समस्याओं में गरीबी, बेरोज़गारी और असमानता के साथ-साथ भ्रष्टाचार, खराब शिक्षा व्यवस्था और अपर्याप्त हेल्थकेयर और सफ़ाई का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दे शामिल हैं। प्रदूषण और पानी की कमी जैसी पर्यावरण संबंधी चिंताएँ, साथ ही लैंगिक भेदभाव और जाति व्यवस्था के प्रभाव जैसी सामाजिक चुनौतियाँ भी प्रमुख मुद्दे हैं।

आर्थिक चुनौतियाँ

- **गरीबी:** आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे रहता है, और ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच अंतर है।
- **बेरोज़गारी:** यह एक बड़ी समस्या है, खासकर युवाओं के लिए, क्योंकि कई पढ़े-लिखे लोग नौकरी ढूँढने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं।
- **असमानता:** धन और अवसर में काफी असमानता है, जो अक्सर जाति और लिंग जैसे कारणों से जुड़ी होती है।

भारत की मुख्य समस्या पर नोट :

इन सबमें सबसे हैरानी की बात यह है कि भारत सरकार इस समस्या का हल ढूँढने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही है और हल ढूँढे बिना ही बेतरतीब ढंग से काम कर रही है और खुद को एक लंबे समय के जाल में फंसा रही है, इसलिए इस पर पूरी तरह से रिव्यू करने की ज़रूरत है ।

ऐसे में समझदारी इसी में होगी कि भारत पहले ऊपर बताई गई समस्या का इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन ढूँढने के लिए पूरी कोशिश करे, उसके बाद ही दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करे। रिक्वेस्ट है कि भारत इस मामले में भी पूरे हालात का रिव्यू करे।

किसी भी राज्य या सभी राज्यों में चुनाव कराना या फिर भारत में 2029 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव बिना किसी सुधार के कराना, भारत की एक के बाद एक अंधेरी सुरंगों में घुसते रहने की आदत को दिखाएगा। आज के समय में, जब हम बिना किसी ज़्यादा फीस के सही कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो गुमनामी में रहने का यह रवैया और भी भयानक लगता है।

ii) भारत, अपनी बड़ी जगह और अमीर विरासत के साथ, न सिर्फ अपने लिए ज़िम्मेदार है, बल्कि अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए भी ज़िम्मेदार है, ताकि पूरी दुनिया की संस्कृति बनी रहे। इसी तरह, दुनिया की भी यह ज़िम्मेदारी है कि वह भारत के साथ सहयोग करे, ताकि वह अपनी परंपरा और संस्कृति को बनाए रखने में काबिल और सक्षम रहे और उन्हें खत्म न होने दे।

इस बारे में मेरे लेटेस्ट पॉडकास्ट: <https://youtu.be/FD21cRfBmjs?si=suRB9Zlnfuh9dBy0>
 जो ज़मीनी हकीकत को छिपाने से ज़्यादा दिखाता है और तारीफ़ के काबिल है।

A.9.3). दुनिया की मुख्य समस्याएं क्या हैं (ओपन सोर्स - गूगल, AI के अनुसार):

i). दुनिया की मुख्य समस्याएं पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों का एक जटिल मिश्रण हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज, गरीबी और संघर्ष को लगातार सबसे ज़्यादा दबाव वाले मुद्दों के तौर पर

हाईलाइट किया जाता है। रोज़गार, जॉब सिक्योरिटी, अकेलापन, ज़्यादा कर्ज़ और रहने की बढ़ती लागत को लेकर चिंताएं आम हैं।

ii). असमानता (इनकम और जेंडर दोनों), गरीबी, खाने और पानी की कमी, और ह्यूमन राइट्स के लिए खतरा।

iii) समुद्र का बढ़ता लेवल, खराब मौसम और इकोसिस्टम और खाने-पीने जैसे रिसोर्स के लिए खतरा। हवा और पानी का प्रदूषण लोगों की सेहत और पर्यावरण पर असर डालने वाली बड़ी समस्याएँ बनी हुई हैं।

iv) हेल्थकेयर और शिक्षा तक पहुंच में असमानता, और ब्रेन ड्रेन में जाना, महामारी और पैन्डेमिक जैसे मुद्दे।

v) लगातार लड़ाई और सुरक्षा के खतरे इलाकों को अस्थिर करते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, और विकास में रुकावट डालते हैं।

vi). सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि दुनिया के बड़े देश, जो खुद को दुनिया का मालिक बताते हैं, और अमेरिका भी, इस समस्या का कोई हल नहीं ढूँढ पा रहे हैं और हल ढूँढे बिना ये (खिलाड़ी, देश और संस्थाएं) दुनिया के तथाकथित तीसरी दुनिया के देशों को सलाह देते रहते हैं या शर्तें तय करते रहते हैं कि ये करो, वो खरीदो, वहां इन्वेस्ट करो और यहीं फोकस करो, चुनाव में जाना है।

दुनिया की मुख्य समस्या पर ध्यान दें : ऐसी अजीब स्थिति में कोई नया व्यक्ति भी कहेगा कि पूरा सिस्टम ही गलत है या गड़बड़ हो गया है और इसे फिर से ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन दुर्भाग्य से बड़े देश और यूनाइटेड नेशन इस बारे में सोचते नहीं दिख रहे हैं।

ऐसे हालात में यह समझा जा सकता है कि जो एजेंसियां गॉड-फादर/मदर बनने की कोशिश कर रही हैं, वे असल में गॉड-फादर/मदर नहीं हैं और दुनिया की समस्या के सामने पहले ही बेचारी साबित हो चुकी हैं, इसलिए उनसे भारत की समस्या को हल करने में मदद की उम्मीद करना मुश्किल है। इसलिए भारत के लोगों और उसकी सरकार को भी इस नज़रिए से पूरे हालात का रिव्यू करना चाहिए और मामले को अपने हाथ में लेना चाहिए।

बी)। समापन प्रस्तुति

B.1). हमने ऊपर बताई गई बातों का हल ढूँढने की कोशिश की और यह कहा जा सकता है कि बड़ों और अनगिनत शुभचिंतकों के आशीर्वाद से हम कई सामाजिक-आर्थिक-धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर बड़े विचार दे पाए हैं और एक प्रैक्टिकल आगे की राह भी बता पाए हैं ताकि एक व्यक्ति और साथ ही मिलकर स्वस्थ, खुशहाल और पवित्र जीवन पाया जा सके (हालांकि इस पर चर्चा करने और डिटेल्स को डॉक्यूमेंट करने में बीस साल से ज़्यादा लग गए)। हमारा मानना है कि धर्म को फिर से ज़िंदा करना और धर्म संस्थान बनाना ही इंसानियत के पास बचा हुआ एकमात्र विकल्प होगा और इसके लिए कई देशों में इसके हिसाब से शासन व्यवस्था में बदलाव करना पहला कदम होगा जिसे शुरू और लागू किया जाएगा।

नीचे साइन करने वाले, नरेंद्र अग्रवाल (उम्र 59 साल) भारत के असली निवासी हैं, ग्रुप Resurrection of dharma के खास व्यक्ति हैं, जिनकी छोटी प्रोफाइल और तैयारी सब्जेक्ट रिक्वेस्ट देने के दावे के पीछे हमारी वेबसाइट: resurrectionofdharma.com पर देखा जा सकता है। वेबसाइट में नीचे दी गई फ्री में डाउनलोड की जा सकने वाली किताबों के ज़रिए बदलाव का एजेंडा है (किताबें ओपन मार्केट में नहीं रखी जाती हैं):

1. मीता लाइफस्टाइल एजेंडा (किताब में समाज, देश और दुनिया के लिए सोशियो-इकोनॉमिक-रिलीजियस-पॉलिटिकल एजेंडा पर 102 टॉपिक हैं), [इस किताब की मैन्युस्क्रिप्ट को भारत के प्रेसिडेंट एक्सिलेंस APJ कलाम ने माना था और 2008 में पाकिस्तान के मौजूदा प्रेसिडेंट के अलावा भारत के कई मिनिस्टर्स और जाने-माने लोगों ने भी इसकी तारीफ की थी]।
2. धार्यते इति धर्म (लाओ त्जु की ताओ ते चिंग का दोबारा अध्ययन), (भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सराहा)
3. डिविनक्रेसी (दिव्य लोकतंत्र) – एम.के. गांधी द्वारा लिखित हिंद स्वराज का पुनरीक्षण – (भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वीकार किया गया)
4. भारत की नज़र में वैश्विक व्यवस्था (हिंदी में- भारत की नज़र में वैश्विक) व्यवस्था
5. काम की बात (हिंदी में – जल, ज़मीन और जंगल पर),
6. वैकल्पिक अर्थव्यवस्था – प्राकृतिक व्यवस्थित अर्थव्यवस्था, अंग्रेज़ी में,
7. धर्म और उससे जुड़े मुद्दों पर कुछ बातें- इसे अपनाने की ज़रूरत (धर्म को अपनाने और इकॉनमी, ज्यूडिशियरी और एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से बनाने के लिए क्या, क्यों और कैसे ज़रूरी है, और इसकी ज़रूरत),
एजेंडा में किताबों के अलावा, कुछ ओपन लेटर और इंटरव्यू और पॉडकास्ट के लिंक भी वहां दिए गए हैं।

B.2). गवर्नेंस में नई जान डालने का समय आ गया है — बाहर से आए सिस्टम की असुरक्षा और अस्थिरता से निकलकर खुद की बनी व्यवस्था के भरोसे की ओर बदलाव । इसके लिए, नीचे साइन करने वाले ने ग्रुप 'रिसरेक्शन ऑफ़ धर्म' और भारत सरकार के साथ पार्टनरशिप का प्रस्ताव रखा है और यह पक्का किया है कि इससे एक स्थिर, सही और दूर की सोचने वाला गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने में मदद मिलेगी जो बिहार और पूरे भारत को उसकी शान वापस लाने में मदद कर सके।

इस समय, नीचे साइन करने वाले यह बताना चाहते हैं कि ये लेटर/कंसल्टेंसी के लिए ऑफर कुछ जाने-माने संतों, साधु, साध्वी, एक्सपर्ट्स और मास्टर्स के कहने पर दिए जा रहे हैं ताकि हिमालय से लेकर भारत के मैदानों और हिंद महासागर तक हमारी सभ्यता की शान वापस लाई जा सके, ताकि हम सब एक हेल्दी, खुशहाल और पवित्र ज़िंदगी जी सकें और दुनिया को भी ऐसा ही करने के लिए गाइड कर सकें।

हम यह बताना चाहते हैं कि हमने लिस्ट में दिए गए सभी लोगों को इस बारे में ईमेल भेज दिए हैं। इसके अलावा, हम यह भी बताना चाहते हैं कि ऐसा ऑफर नेपाल, इंडोनेशिया और दूसरी सरकारों को भी भेजा जा चुका है और जल्द ही भेजा जाएगा।

आखिर में हम यह कहना चाहेंगे कि 'धर्म का पुनरुत्थान' ग्रुप बिहार और पूरे भारत के लोगों को आगे आने और इंडिया डैट इज़ भारत को एक बार फिर से एक हेल्दी, खुशहाल और पवित्र देश बनाने की हमारी कोशिश में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है - “एक मालिक का गर्व और पड़ोसियों का गाइड”।

ऊपर सबमिट किया गया है,
भगवान भारत को आशीर्वाद दें,

सादर

नरेंद्र अग्रवाल

धर्म के पुनरुत्थान के लिए,

वेबसाइट: resurrectionofdharma.com, तारीख: 21.11.2025, दिल्ली, इंडिया